17-02-2024

राष्ट्रीय आयुष मिशन की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक

सुर्खियों में क्यों?

- 15 फरवरी 2024 को केन्द्रीय आयुष और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के पटना में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित छह राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में भाग लिया|

संबंधित प्रमुख बिंदु

- आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत अपने संबंधित राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। ध्यान रहे, सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (NAM) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में वर्ष 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है।
- केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023-24 तक एनएएम के एक घटक के रूप में राज्य / केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से आयुष मंत्रालय द्वारा 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों (एएचडब्ल्यूसी) के संचालन को मंजूरी दी गई है।
- हाल ही में एनएएम योजना के लिए बजटीय प्रावधान बढ़ाकर 1200 करोड़ रुपये कर दिया गया है | ध्यान रहे, आयुष मंत्रालय ने 2014-15 से अब तक एनएएम के तहत 07 राज्यों (बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) को 1712.54 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- एनएएम के तहत, मंत्रालय ने 2022-23 के दौरान अयोध्या में एक नए आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, वाराणसी में नए होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के हावड़ा में योग और प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए भी सहयोग दिया है।

राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में

- इस मिशन को सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग

द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिये शुरू किया गया था। वर्तमान में इसे आयुष मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है।
- NAM का उद्देश्य उन राज्यों में मौजूदा आयुष शैक्षणिक संस्थानों का उन्नयन और नए आयुष कॉलेजों की स्थापना के माध्यम से आयुष शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।
- इस योजना में भारतीयों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये आयुष क्षेत्र का विस्तार शामिल है। यह मिशन देश में विशेष रूप से कमज़ोर और दूर-दराज़ के क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ / शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर स्वास्थ्य सेवाओं में अंतराल को संबोधित करता है।

श्रीलंका और मॉरीशस में UPI सेवाओं की शुरुआत

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री रानिल विक्रमसिंघे और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका तथा मॉरीशस में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (Unified Payment Interface - UPI) सेवाओं एवं रुपे कार्ड (RuPay card) सेवाओं के शुभारंभ का मॉरीशस में उद्घाटन किया।
- इस परियोजना को भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत मॉरीशस तथा श्रीलंका के साझेदार बैंकों/गैर-बैंकों के साथ

NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड(NPCL) द्वारा विकसित तथा निष्पादित किया गया है।

रुपे कार्ड (RuPay card) एवं UPI क्या होता है?

- रुपे कार्ड भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा विकसित एक भुगतान प्रणाली और वित्तीय सेवा उत्पाद है जिसका उपयोग पूरे भारत में ATMs, पॉइंट ऑफ सेल(PoS) उपकरणों और ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर किया जा सकता है।
- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) वर्ष 2016 में NPCI द्वारा विकसित एक डिजिटल और वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। यह प्रणाली IMPS (तत्काल भुगतान सेवा) बुनियादी अवसंरचना पर बनाया गया है और उपयोगकर्त्ताओं को किसी भी दो पक्षों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है।
- UPI कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को एक मोबाइल एप्लिकेशन में विलय करने की अनुमति देता है।
- UPI भुगतान स्वीकार करने वाले देश फ्राँस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, श्रीलंका, सिंगापुर, भूटान और नेपाल हैं। जबकि रुपे कार्ड स्वीकार करने वाले देश में मॉरीशस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात है|

NPCI के बारे में

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की स्थापना भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अनुसार वर्ष 2008 में की गई थी।
- इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा देश के खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का प्रबंधन करने के लिए किया गया है|
- यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में लिस्टेड है।
- इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में है।

स्मार्ट ग्राम पंचायत परियोजना

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के बेगुसराय

NEW OPTIONAL FOUNDATION COURSE FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM STARTING FROM 16TH FEBRUARY, 2024

ज़िले के पपरौर ग्राम पंचायत में 'स्मार्ट ग्राम पंचायत : ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति' परियोजना का उद्घाटन किया।

स्मार्ट ग्राम पंचायत के बारे में

- यह पहल ग्रामीण भारत में डिजिटल सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की कनेक्टिविटी में परिवर्तन के साथ बेगुसराय की सभी ग्राम पंचायतों तक PM-वाणी (प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस) सेवा पहुँचाना है। ध्यान रहे, बेगूसराय अब PM-वाणी योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को वाई-फाई सेवाओं से लैस करने वाला बिहार का पहला ज़िला बन गया है।
- इस परियोजना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वित्त पोषित किया गया है। इसका लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बेगुसराय और रोहतास में ग्राम पंचायतों तक पीएम-वाणी सेवाओं का विस्तार करना है। ध्यान रहे, RGSA पंचायती राज मंत्रालय की एक योजना है जिसे वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था।
- इसका कार्यान्वन बीएसएनएल के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है|
- यह छात्रों, किसानों, कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल में ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने पर केंद्रित है।
- इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन को पाटना, स्थानीय स्वशासन में उत्तरदायित्व और दक्षता को बढ़ावा देना तथा डिजिटल फुटप्रिंट के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।

पीएम-वाणी क्या है?

- पीएम-वाणी (PM-WANI), देश भर में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक मज़बूत डिजिटल संचार अवसंरचना स्थापित करने के लिये सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट तक पहुँच में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई एक प्रमुख योजना है|
- इस योजना को दिसंबर 2020 में दूरसंचार विभाग (Department of Telecom - DoT) द्वारा लॉन्च की गई थी|
- इस योजना के तहत कोई भी इकाई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, 2018 (National Digital Communications Policy - NDCP) के अनुरूप हॉटस्पॉट स्थापित कर सकती है।
- यह जोजना ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड उपलब्धता और सामर्थ्य को बढ़ावा देगा, उद्यमशीलता तथा डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देगा।
- यह भारतनेट परियोजना का पूरक है। यह 5G जैसी मोबाइल प्रौद्योगिकियों की तुलना में इंटरनेट एक्सेस हेतु एक किफायती और सुविधाजनक विकल्प प्रदान कर सकता है। यह इंटरनेट बाज़ार में नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर सकता है।

NEW OPTIONAL FOUNDATION COURSE FOR ENGLISH & HINDI MEDIUM STARTING FROM 16TH FEBRUARY, 2024

बिहार में कालूघाट IWT टर्मिनल का उद्घाटन

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बिहार के बेतिया में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल (IWT) और दो सामुदायिक घाटों का उद्घाटन किया।

संबंधित प्रमुख बिंदु

- कालूघाट बिहार के सारण जिले में गंगा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जो इस क्षेत्र के परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभर रहा है।
- यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-19 तक अपनी सीधी पहुंच के साथ, टर्मिनल कार्गो आवाजाही के लिए, विशेष रूप से रक्सौल और उत्तरी बिहार के भीतरी इलाकों के माध्यम से नेपाल जाने वाले शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में कार्य करता है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-37 के माध्यम से नेपाल और भारत को जोड़ने के लिए गंडक नदी पर मंगलपुर और बेतिया में फ्लोटिंग पोंटून घाट स्थापित किए गए हैं, जो 3.33 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार हुआ है।
- ध्यातव्य है कि जल मार्ग विकास परियोजना के एक भाग के रूप में, भारतीय अंतर्गेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (IWT) ईकोसिस्टम के विकास की शुरुआत की है।
- इसके तहत नौवहन के निर्माण के साथ-साथ कार्गो हैंडलिंग, निर्बाध नौवहन के लिए फ़ेयरवे विकास करना, रात्रि नौवहन और आरआईएस सुविधाओं के प्रावधान के लिए मल्टीमॉडल टर्मिनलों (एमएमटीएस) और इंटरमॉडल टर्मिनलों (आईएमटीएस) के निर्माण की जाएगी।
- गौरतलब है कि सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत जलमार्गों की क्षमता को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत 111 (5 मौजूदा और 106 नए) राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) की घोषणा शामिल है।